



भारत का राजपत्र The Gazette of India

बसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

(N) 30/4/88

सं. 96]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 1988/फाल्गुन 12, 1909

No. 96]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 1988/PHALGUNA 12, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(विदेशी कर प्रभाग)

नई दिल्ली 2 मार्च 1988

अधिसूचना

आयकर

(1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते
हैं, यह निर्देश देता है कि उक्त अनुपूर्व प्रोत्ताकोल के मधी उपबन्धों को
भारत के मध्य में कार्यन्वित किया जाएगा।

उपबन्ध

(कृपया यहाँ अनुपूर्व प्रोत्ताकोल अतः स्थापित करें)

मा. का. नि. 321 (अ) - आय पर कर का बावत दाहरे कराधान
में बचने और राजस्व वित्तिय अपवचन का रोकने के लिए भारत सरकार और
बेल्जियम के मन्त्र 3 बत करण का उपानरित करने वाला इससे
उपबन्ध अनुपूर्व प्रोत्ताकोल और 7 फरवरी 1974 का ब्रूमन में हस्ता-
क्षरित प्रातीकाश यह प्रमाणित करने हुए कि प्रत्येक मन्त्रिकाय राज्य में
उन अनुपूर्व प्रातीकाश 10 का अपेक्षानुसार समचित प्रातया
की परा किया गया था पत्र 2 आदान प्रदान के पश्चात 23 जनवरी
1988 को प्रवृत्त हुआ है।

[स. 7759/फा. म. 505/187 म. पी. टी.]

प. र. मन्त्र मन्त्र मन्त्र

उपबन्ध

आय पर कर के मध्य में दाहरे कराधान के परिणाम और वित्तीय
अपवचन के रोकने के लिए भारत सरकार और बेल्जियम सरकार के बीच
हुए करण और प्रातीकोल में जिन पर 7 फरवरी, 1974 का ब्रूमन में
हस्ताक्षर किए गए मन्त्रिकान करने वाला अनुपूर्व प्रोत्ताकोल।

अतः अब कन्दय सरकार आयकर सविनयम 1961 (1961 का
43) का धारा 90 और कानून (नाम) अतिरिक्त अधिनियम 1964

भारत सरकार

अनुच्छेद 3

और

वैजयंकर सरकार से

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और विविध अपवर्धन को रोकने के लिए भारत सरकार और वैजयंकर सरकार के बीच हुए करार (जिसे इसके बाद "करार" के रूप में उल्लिखित किया गया है), और प्रोटोकॉल में, जिन पर 7 फरवरी, 1974 को ब्रुसल्स में हस्ताक्षर किए गए थे। कथित पहलुओं से संशोधन करने की इच्छा रखते हुए, इस प्रयोजन के लिए एक अनुपूरक प्रोटोकॉल सम्पन्न करने का निर्णय किया है और वे निम्नलिखित अनुच्छेदों पर सहमत हुई हैं :

अनुच्छेद 1

करार के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के मूलपाठ को हटा कर उसके स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा:

"3 किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उन व्ययों की कटौतियों की स्वीकृति दी जाएगी, जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजन के लिए किए गए हों, चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र परन्तु जिन संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन स्थित है उसके बाहर किए गए कार्यपालीय और सामान्य प्रशासनिक व्ययों के लिए इस प्रकार मंजूर की गई कटौतियाँ उस राज्य के कराधान कानूनों के उपबंधों के अनुसार और उनकी सीमाओं के अन्वयान होंगी, परन्तु जहाँ, उस संविदाकारी राज्य के कराधान कानूनों में ऐसे व्ययों की कटौत के संबंध में व्यवस्था नहीं है, जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है, मंजूर की जाने वाली कटौती स्थायी संस्थापन के ऐसे शुद्ध लाभों के 5 प्रतिशत भाग से अधिक नहीं होगी, जो, कटौती से पूर्व संगणित किए गए हों। परन्तु स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में), पेटेंटो अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले रायल्टियाँ, फीस अथवा अन्य ऐसी ही अदायगियों के रूप में, अथवा की गयी विशिष्ट सेवाओं अथवा प्रबंध के लिए कर्मशान के रूप में अथवा, बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर व्याज के रूप में यदि कोई रकम अदा की गई हों तो, उनके संबंध में ऐसी किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में उन रकमों को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी को, (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप में) स्थायी संस्थापन द्वारा पेटेंटो अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले से रायल्टियाँ, फीस अथवा अन्य ऐसी ही अदायगियों के रूप में अथवा की गयी विशिष्ट सेवा के लिए अथवा प्रबंध के लिए कर्मशान के रूप में अथवा, बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, अन्य मामलों में, उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा उस के अन्य कार्यालयों में से किसी को उधार दिए गए धन पर व्याज के रूप में उद्यम के प्रधान कार्यालय अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से कितना प्रभावित हो गई हो।"

अनुच्छेद 2

करार के अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 3 का मूलपाठ हटा कर उसके स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :

"3. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम को दूसरे संविदाकारी राज्य से 'नगरीय यातायात' में पोल-परिवहन से हुई आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा, परन्तु ऐसी आय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रभावी कर से, ऐसे कर के 50 प्रतिशत भाग के बराबर की रकम कम कर दी जाएगी।"

करार के अनुच्छेद 10 का मूल पाठ हटा कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :

"1 जो कंपनी एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, उसके द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किए गए लाभांशों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2 तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी निवासी है परन्तु यदि, उस राज्य के कानूनों के अनुसार, लाभांशों का हितभागी स्वामी एक कंपनी है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, तो उस प्रकार लगाया गया कर लाभांशों की सकल रकम के 15 प्रतिशत भाग में अधिक नहीं होगा।

यह पैराग्राफ उस लाभों के संबंध में कंपनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा, जिनमें से लाभांश अदा किए जाते हैं।

3. पैराग्राफ 2 में कर की दर में घटौती सम्बन्धी पद्धति इस अनुपूरक प्रोटोकॉल के लागू होने के बाद किए गए निवेशों से उत्पन्न होने वाले लाभांशों के संबंध में लागू होंगे।

4. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "लाभांशों" पद में शेयरों, "जाउसेंस" शेयरों अथवा "जाउसेंस" अधिकारों, खनन-शेयरों, संस्थापकों के शेयरों अथवा ऐसे अन्य अधिकारों में, जो श्रद्धा-दावे नहीं हैं, और भागीदारी लाभ हो, प्राप्त व्यय तथा अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय अभिप्रेत है, जिन पर कराधान व्यवस्था उसी प्रकार से लागू होती है जिन प्रकार की शेयरों से प्राप्त आय के मामले में उस राज्य के कानून के तहत होती है जिसमें वितरण करने वाली कंपनी निवासी है। इस पद का अभिप्राय उस आय से भी है—चाहे वह व्याज के रूप में अदा की गई हो—जो शेयर पूंजी वाली ऐसी किसी कंपनी भिन्न कंपनी के, जो वैजयंकर की निवासी सदस्यों द्वारा निवेशित पूंजी पर आय के शीर्षों के अंतर्गत वसूली है।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में व्यापार करता है जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी, वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से, निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवायें करता है और जिस आरिता के बारे में लाभांशों की अदायग की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से पताची रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में अध्याय 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे।

6. जहां कोई कंपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वह कंपनी द्वारा ऐसे व्यक्ति को, जो प्रयोजननिष्ठ राज्य का निवासी है, अदा किए गए लाभांशों पर, जहां तक कि ऐसी धारिता को छोड़कर जिसके बारे में लाभांशों की अदायग की जाती है, वह उस दूसरे राज्य में स्थित भग्नापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। उस दूसरे राज्य में न तो कोई कर लगाया जा सकेगा और न ही कंपनी के अतिरिक्त लाभों पर अतिरिक्त लाभ-कर का किस्म का कोई कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अतिरिक्त लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हो।

अनुच्छेद 4

करार के अनुच्छेद 11 का मूलपाठ हटा कर उसके स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा:

“1 एक सविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले अथवा दूसरे सविदाकारी राज्य के निवासियों का अदा किए जाने वाले व्याज पर कर उस दूसरे राज्य में लग सकेगा।

2 तथापि, इस प्रकार के व्याज पर उम सविदाकारी राज्य में भा और उम राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा जिस राज्य में यह उद्भूत होता है परन्तु यदि व्याज का हितभागी स्वामी दूसरे सविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रभावित कर इस अनुपूरक प्रोतीकाल के लागू होने की तारीख के बाद दिए गए कर्ज अथवा जारी किए गए ऋण के संबंध में व्याज की सकल राशि के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3 इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “व्याज” पद का अभिप्राय हर प्रकार के ऋण-दावा से प्राप्त आय से, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं और चाहे उनको देनदार के लामो में भारीदारों का अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय से और वधपत्ता अथवा ऋण-पत्रों से, जिनमें ऐसी प्रतिभूतियाँ, बध-पत्रों अथवा ऋण-पत्रों से सम्बद्ध प्रीमियम और पुरस्कार भी शामिल हैं, प्राप्त आय से है तथापि “व्याज” पद में, इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, देर में अदायगी के लिए अर्पण्य प्रभार शामिल नहीं होंगे, और न ही अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 4 के दूसरे वाक्य के अंतर्गत लाभान के रूप में माना गया व्याज भी शामिल होगा।

4 पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उम स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि व्याज का हितभागी स्वामी सविदाकारी राज्य का निवासी होने से, दूसरे सविदाकारी राज्य में जिसमें व्याज उत्पन्न हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम में व्यापार चलाता हो अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान में स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाये करता हो और जिस ऋण-दावे के बारे में व्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान में प्रारंभिक रूप से सम्बद्ध है। ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबन्ध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

5 किसी सविदाकारी राज्य में व्याज उद्भूत हुआ तब माना जाएगा जब व्याज अदा करने वाला स्वयं सविदाकारी राज्य, कोई राजनीतिक उप-मंडल, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उम राज्य का कोई निवासि हो। किन्तु जहाँ व्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह सविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, सविदाकारी राज्य में उसका एक स्थायी संस्थापन अथवा एक निश्चित स्थान है जिसमें संबंध में वह ऋण लिया गया हो जिन पर व्याज की अदायगी की गई है, और इस प्रकार का व्याज ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तब वह व्याज उम सविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6 जहाँ व्याज अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण व्याज की रकम उम ऋण-दावे की ध्यान में रखने हुए जिसके लिए उक्त रकम अदा की गई हो उम रकम से बढ़ जाती है, जिसके द्वार में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई हो। वहाँ इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदायगियों के अतिरिक्त भाग पर, उम सविदाकारी राज्य में उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाना जारी रहेगा जिसमें व्याज उत्पन्न होता है।”

अनुच्छेद 5

1 करार के अनुच्छेद 12 के शीर्षक और मूलपाठ को हटाकर उनके स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा

“राज्यलियाँ” और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क

1 एक सविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे सविदाकारी राज्य के निवासियों का अदा की गयी राजलियों और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्कों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2 तथापि ऐसी राजलियों और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क पर उम सविदाकारी राज्य में भी कर और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसमें वे उद्भूत होते हैं, बशर्ते कि जहाँ राजलियों और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्कों का लाभकारी स्वामी अन्य सविदाकारी राज्य का निवासी है तथा राजलियाँ तथा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क इस अनुपूरक प्रोतीकाल के लागू होने की तारीख के बाद प्रदान किए गए अधिकार अथवा संपत्ति के संबंध में अदा किए जाते हैं, अथवा किसी सविदा के अर्धीन हस्ताक्षर किए जाते हैं तो इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी राजलियों और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्कों की सकल रकम के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3 (क) इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “राजलियाँ” पद से साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियाँ, जिनमें चरचित्त-चित्रों तथा दूरदर्शन चित्रों शामिल हैं, के कॉपीराइट के किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा माडल, प्लान, गैज फॉर्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफल के रूप में अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त किसी भी प्रकार का अदायगी अभिप्रेत है।

(ख) इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क” पदवाली से प्रबंधकीय तकनीकी अथवा परामर्शदाता स्वरूप की सेवाओं का, जिनमें तकनीकी अथवा अन्य कामों की सहायों की व्यवस्था भी सम्मिलित है, प्रतिफल में अदायगियाँ करने वाले व्यक्ति के कर्मचारी का अदायगी करना तथा अनुच्छेद 15 में वर्णित स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति को का गई अदायगी अभिप्रेत है।

4 पैराग्राफ 1 और 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि राजलियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्कों का लाभकारी स्वामी, जो एक सविदाकारी राज्य का निवासी है और अन्य सविदाकारी राज्य में, जिसमें राजलियाँ तथा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क उद्भूत होते हैं, वहाँ पर स्थित स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उम अन्य राज्य में वहाँ पर स्थित निश्चित स्थान से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएँ करता है, तथा अधिकार अथवा संपत्ति में संबंध में राजलियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क अदा किए जाते हैं ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ कारण रूप से संबंध है। ऐसे मामले में यथास्थिति, अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपबन्ध लागू होंगे।

5 किसी सविदाकारी राज्य में राजलियाँ और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क उद्भूत हुए मान जायेंगे, यदि राजलियाँ और शुल्क अदा करने वाला स्वयं वह राज्य, कोई राजनीतिक उपमंडल, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा राज्य का कोई निवासी हो। परन्तु जहाँ तकनीकी सेवाओं के लिए राजलियाँ अथवा शुल्क अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह सविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं सविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान हो जिसके संबंध में अदायगी करने की जिम्मेदारी ली गई हो और उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा अदायगियाँ की जाती हो, तब तकनीकी सेवाओं के लिए राजलियाँ अथवा शुल्क उम राज्य में उद्भूत हुए मान जायेंगे जिसमें स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6 जहाँ अदायगी करने वाले और लाभकारी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष प्रकार का संबंध

हूँने के कारण अथवा की गई रायस्टिया अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्कों की रकम उमने ऐसे हस्तमाल, अधिकार, सूचना तथा तकनीकी सेवाओं का ध्यान में रखते हुए जिसके लिए वे रायस्टिया अथवा शुल्क अथवा विग गए हो उस रकम में बट जाने हैं जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अथवा करने वाले और हितधारी स्वामी के साथ सहमति हो गयी होती वहा इस अनुच्छेद के उपबंध केअन अन्तिम धर्णिन रकम पर लागू हाने । ऐसे मामले में रायस्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्कों की अदायगियों के अधिभाग पर उस भविष्यकारी राज्य में, जिसमें रायस्टिया अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क उद्भूत हुए हैं, उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

2 कर्ग के अनुच्छेद 13 को हटा दिया जाता है ।

अनुच्छेद 6

कर्ग के अनुच्छेद 15 के मूल पाठ का हटा कर उमने स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा

स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएँ

1 बेल्जियम के किसी निवासी द्वारा भारत में की गई व्यक्ति सहाय अथवा इसी प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त की गई आय पर भारत में कर लगाया जा सकेगा यदि—

(क) वह सगत पूर्ववर्ती वर्ष में कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए भारत में उपस्थित रहा हो, अथवा

(ख) अपना सहाय अथवा कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उसे भारत में एक निश्चित स्थान नियमित रूप में उपस्थित रहा हो,

परन्तु प्रत्येक मामले में वह केवल उतनी रकम पर ही लगाया जा सकेगा जो उन सेवाओं अथवा कार्यकलापों के कारण प्राप्त हुई मानी जा सकती हो ।

2 भारत के किसी निवासी द्वारा बेल्जियम में की गई व्यक्ति सहाय अथवा इसी प्रकार के अन्य स्वतंत्र कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आय पर बेल्जियम में कर लगाया जा सकेगा यदि—

(क) वह सगत वर्ष सगत यात्रा अवधि में कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए बेल्जियम में उपस्थित रहा हो अथवा

(ख) अपना सहाय अथवा कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उस बेल्जियम में एक निश्चित स्थान नियमित रूप में उपस्थित रहा हो

परन्तु प्रत्येक मामले में वह केवल उतनी रकम पर लगाया जा सकेगा जो उन सेवाओं अथवा कार्यकलापों के कारण प्राप्त हुई मानी जा सकती हो ।

3 व्यक्ति सहाय सेवाएँ वास्तव में स्वतंत्र वैज्ञानिक सांख्यिक कलात्मक, शैक्षणिक अथवा प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सा, श्रमिक, शैक्षणिक वास्तुकारों, दंत-चिकित्सकों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलापों का शामिल हैं ।”

अनुच्छेद 7

इस कर्ग के अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 3 के उपपैराग्राफ (ग) के मूल पाठ को हटा कर उमने स्थान पर निम्नलिखित का रखा जाएगा

“(ग) जहां बेल्जियम का कोई निवासी, अनुच्छेद 10 में उल्लिखित ऐसे लाभों के रूप में (जो इस पैराग्राफ के उपपैराग्राफ

(ख) के द्वारा आने वाले लाभों नहीं हैं) अथवा इस

कर्ग के अनुच्छेद 11 में उल्लिखित व्यय के रूप में अथवा इस कर्ग के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 3(क) में उल्लिखित रायस्टियों के रूप में आय प्राप्त करता है, तो बेल्जियम में आय पर सगत वर्ष बेल्जियम के कर के प्रति, लागू वह अनुदान प्रभावित किया गया हो अथवा छोड़ दिया गया हो, जमा की मजदूरी देगा । इस प्रकार मजदूरी को जाने वाला जमा की रकम की संग्रहता, भारणीय कर यदि कोई हो, की कटौती के बाद प्राप्त होने वाले लाभों तथा अथवा रायस्टियों की सक्त रकम पर की जाएगी । इस प्रकार को जाने वाली कटौती का दर लाभों तथा व्यय के मामलों में 15 प्रतिशत तथा रायस्टियों के मामलों में 20 प्रतिशत से कम नहीं होगा ।”

अनुच्छेद 8

इस कर्ग के प्रास्ताविक के पैराग्राफ (ग) के मूल पाठ को हटा कर उमने स्थान पर निम्नलिखित का रखा जाएगा

“(ग) अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 2 द्वारा व्यवस्थित कर की दर वित्तीय व्यवस्था का ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है जो धनगत में बेल्जियम के राष्ट्रीय कानून के अनुरूप उन लाभों पर लागू होती है जो बेल्जियम के निवासी किसी कंपनी का अनिवार्य कंपनियों की शेयर पूंजी में रखाया शेयर धारिता में प्राप्त होते हैं ।

यद्यपि इस पक्ष में बेल्जियम के राष्ट्रीय कानून में कोई परिवर्तन हो जाने से यदि बेल्जियम में लाभों आय की कर संबंधी व्यवस्था प्रभावित होती है तो अनुच्छेद 10 में व्यवस्थित 15 प्रतिशत की घटा कर लागू नहीं होगा ।

अनुच्छेद 9

इस कर्ग के प्रास्ताविक के पैराग्राफ (घ) में लाभों अथवा व्यय’ शब्दों के स्थान पर लाभों, व्यय अथवा रायस्टिया’ शब्द रखे जाएंगे ।

अनुच्छेद 10

1 यह अनुसूक्त प्रास्ताविक सविशेष राज्य में से प्रत्येक में प्राप्त विधियों के अनुसार अनुमानित किया जाएगा । यह अनुसूक्त प्रास्ताविक प्रत्येक सविशेष राज्य में विहित धाराएं पूरा हो जाने के प्रमाणों पर ही विनिर्णय के तम दिनांक परवान लागू होगा तथा वह विनिर्णय जम्मू में होगा ।

2 इस अनुसूक्त प्रास्ताविक के उद्देश्य

(क) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में पत्रों का विनिर्णय होता है, उमने जनवरी मास के प्रथम दिन का अथवा तत्पश्चात् प्रारम्भ होने वाले किसी निश्चित वर्ष के दौरान प्राप्त आय के संबंध में;

(ख) बेल्जियम में

(1) जिस कैलेंडर वर्ष में पत्रों का विनिर्णय होता है, उमने जनवरी मास के प्रथम दिन का अथवा तत्पश्चात् जमा की गयी अथवा मंदिर आय के संबंध में स्वीकृत पर देय समस्त कर के संबंध में

(11) उमने कैलेंडर वर्ष के दिसम्बर मास के 31वें दिन का अथवा तत्पश्चात् समाप्त होने वाले किसी वर्ष के अथवा अथवा के दौरान प्राप्त आय के संबंध में स्वीकृत पर देय कर से भिन्न आय समस्त कर के संबंध में,

लागू होगा ।

3. यह अनुपूरक प्रोटोकॉल तब तक लागू रहेगा जब तक कि 7 फरवरी 1974 को ब्रसेल्स में हस्ताक्षरित करार तथा प्रोटोकॉल प्रभावी हो तथा उसका करार और प्रोटोकॉल का समाप्ति की दशा में, यह उनके साथ ही समाप्त होगा।

इसके साथ ही, इसके लिए सम्यक्तः प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने वर्तमान अनुपूरक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

‘नई दिल्ली में 1988 के अक्टूबर मास के 20वें दिन का दो मूल प्रतियों में हिन्दी, अंग्रेजी, फ्रान्सीसी और नीदरलैंड की भाषाओं में सम्पन्न हुआ, सभी चारों पाठ समानतः प्रामाणिक होंगे। इन पाठों के बीच किसी भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होगा।’

(कु. ना. सिंह)

(ज. हॉलान्ड्स वान त्रुग)

भारत की सरकार

बेल्जियम की सरकार

की ओर से

की ओर से

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(FOREIGN TAX DIVISION)

New Delhi, the 2nd March, 1988.

NOTIFICATION

INCOME-TAX

G. S. R. 321 (E) —Whereas the annexed Supplementary Protocol modifying the Agreement between the Government of India and the Government of Belgium for the Avoidance of Double Taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and the Protocol signed at Brussels on February 7, 1974, has come into force on the 23rd January, 1988 after the exchange of letters certifying that the proper procedure was fulfilled in each Contracting State as required by Article 10 of the said Supplementary Protocol.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Supplementary Protocol shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE

(Please insert the Supplementary Protocol here)

[No. 7788 F. No. 505/1/87-F. T. D.]

P. K. APPACHOO, Jt. Secy.

SUPPLEMENTARY PROTOCOL MODIFYING THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF BELGIUM FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PROTOCOL SIGNED AT BRUSSELS ON FEBRUARY 7, 1974.

The Government of India
and

The Government of Belgium.

Desiring to modify in certain respects the Agreement between the Government of India and the Government of Belgium for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (hereinafter referred to as “the Agreement”) and the Protocol signed at Brussels on February 7, 1974, have decided to conclude for this purpose a Supplementary Protocol and have agreed upon the following Articles :

ARTICLE 1

The text of paragraph 3 of Article 7 of the Agreement is deleted and replaced by the following :

“3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere ; but the deduction so allowed for executive and general administrative expenses incurred outside the Contracting State in which the permanent establishment is situated shall be in accordance with the provisions of and subject to the limitation of the taxation laws of that State. Where, however, the taxation laws of the Contracting State where the permanent establishment is situated, do not provide for the deduction of such expenses, the deduction to be allowed shall not exceed 5 per cent of the net profit of the permanent establishment as computed before the deduction. However, no deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed, or for management, or except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.”

ARTICLE 2

The text of paragraph 3 of Article 8 of the Agreement is deleted and replaced by the following :

“3. Income of an enterprise of a Contracting State derived from the other Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in the other Contracting State, but the

tax chargeable in that other Contracting State on such income shall be reduced by an amount equal to 50 per cent of such tax."

ARTICLE 3

The text of Article 10 of the Agreement is deleted and replaced by the following :

"1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a company which is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The provisions regarding the reduction in the rate of tax in paragraph 2 shall apply in respect of dividends arising out of investments made after the entry into force of the Supplementary Protocol modifying this Agreement.

4. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident. This term means also income—even paid in the form of interest—which is taxable under the head of income on capital invested by the members of a company other than a company with share capital, which is a resident of Belgium.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

6. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company to a person who is a resident of the first mentioned State, except insofar as the holding in

respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment of a fixed base situated in that other State nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid on the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State."

ARTICLE 4

The text of Article 11 of the Agreement is deleted and replaced by the following :

"1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest in respect of a loan advanced or debt created after the date of entry into force of the Supplementary Protocol modifying this Agreement.

3. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, however, the term "interest" shall not include for the purpose of this Article penalty charges for late payment nor interest regarded as dividends under the second sentence of paragraph 4 of Article 10.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political sub-division, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid is incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed

to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable in the Contracting State in which the interest arises according to the law of that State."

ARTICLE 5

1. The title and the text of Article 12 of the Agreement are deleted and replaced by the following :

"Royalties and fees for technical services

"1. Royalties and fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

"2. However, such royalties and fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State provided that where the beneficial owner of the royalties or fees for technical services is a resident of the other Contracting State and the royalties and fees for technical services are paid in respect of a right or property which is granted, or under a Contract which is signed, after the date of entry into force of the Supplementary Protocol modifying this Agreement the tax so charged shall not exceed 30 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

"3. (a) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph and television films, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience

(b) The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any kind to any person, other than payments to an employee of the person making the payments and to any individual for independent personal services mentioned in Article 15 in consideration for services of a managerial, technical or consultancy nature, including the provision of services of technical or other personnel

"4 The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties

or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which, or the contract under which, the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 15, as the case may be, shall apply.

"5. Royalties and fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to make the payments was incurred and the payments are borne by such permanent establishment or fixed base, then the royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

"6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for technical services, having regard to the use, right, information or technical services for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the royalties or fees for technical services shall remain taxable in the Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise according to the law of that State."

2 Article 13 of the Agreement is deleted.

ARTICLE 6

The text of Article 15 of the Agreement is deleted and replaced by the following :

"Independent personal services

"(1) Income derived by a resident of Belgium in respect of professional services rendered or other independent activities of a similar character performed in India may be taxed in India if

(a) he is present in India for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days during the relevant previous year; or

(b) he has a fixed base regularly available to him in India for the purpose of performing his services or activities;

but in each case only so much of the income as is attributable to those services or activities.

"(2) Income derived by a resident of India in respect of professional services rendered or other independent activities of a similar character performed in Belgium may be taxed in Belgium if

- (a) he is present in Belgium for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days during the relevant taxable period; or
- (b) he has fixed base regularly available to him in Belgium for the purpose of performing his services or activities;

but in each case, only so much of the income as is attributable to those services or activities.

"(3) The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants."

ARTICLE 7

The text of sub-paragraph (c) of paragraph 3 of Article 23 of the Agreement is deleted and replaced by the following :

- (c) Where a resident of Belgium receives income by way of dividends referred to in Article 10 (not being dividends covered by sub-paragraph (b) of this paragraph) or interest referred to in Article 11 or royalties referred to in paragraph 3, (a), of Article 12 of this Agreement, Belgium shall allow, against the Belgium tax chargeable on such income, a credit in respect of tax chargeable in India on such income, whether actually charged or spared. The amount of the credit to be so allowed shall be computed on the gross amount of dividends, interest or royalties so received after deduction of Indian tax, if any, at a rate which shall not be less than 15 per cent in the case of dividends and interest and 20 per cent in the case of royalties."

ARTICLE 8

The text of paragraph (c) of the Protocol to the Agreement is deleted and replaced by the following:

- "(c) The rate of tax provided by paragraph 2 of Article 10 has been fixed in consideration of the fiscal treatment presently applicable under Belgium national law to dividends derived by a company which is a resident of Belgium from permanent holidays in the share capital of non-resident companies. However, in the case of any change of the Belgium national law in this respect affecting the tax treatment of the dividend income in Belgium, the reduced rate of 15 per cent provided in Article 10 would no longer apply."

ARTICLE 9

In paragraph (d) of the Protocol to the Agreement, the words "dividends or interest" shall be substituted for the words "dividends, interest or royalties".

ARTICLE 10

1. This Supplementary Protocol shall be approved in accordance with the laws in force in each of the Contracting States. It shall enter into force thirty days after the exchange of letters certifying that the proper procedure was fulfilled in each Contracting State. The exchange of letters shall take place at Brussels

2. The provisions of this Supplementary Protocol shall have effect :

- (a) In India, in respect of income derived during any previous year beginning on or after the 1st day of January of the calendar year in which the exchange of letters takes place;
- (b) In Belgium :
 - (i) as respect all tax due at source on income credited or payable on or after the 1st day of January of the calendar year in which the exchange of letters takes place;
 - (ii) as respect all tax other than tax due at source on income derived during any taxable period ending on or after the 31st day of December of the said calendar year.

3. This Supplementary Protocol shall remain in force as long as the Agreement and the Protocol signed at Brussels on February 7, 1974 are in effect and in the event of termination of such Agreement and Protocol, it shall terminate simultaneously with them.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed the present Supplementary Protocol.

Done on this 20th day of October, 1984 in New Delhi on two original copies each in Hindi, English, French and Netherlands languages, all the four texts being equally authentic. In case of divergence between the texts, the English text shall be the operative one.

For the Government of India

(K. N. SINGH)

For the Government of Belgium

(J. HOLLANIS VAN LOOCKE)